to Kerala to assess the things and to give immediate relief. The problem is the terrain of Kerala is different. ...*(interruptions)*... Unless a team from the Centre goes there and makes the assessment, the Central Government won't give the assistance. The terrain in Kerala is different because within 24 hours the water will reach the sea. That problem is there. So, immediate relief should be given. Secondly, regarding the assistance to be given to the families of those who had died, in Gujarat, a gesture was shown, during the natural calamities, in Gujarat, the victims had been given money from the Prime Minister's Relief Fund. My humble submission is that assistance should be given from the Prime Minister's Relief Fund to the victims of the flood in Kerala also.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Shri Poulose—not here. Shri Ahammed Haji—not here. Shri Lajpat Rai—not here. Sardar Balwinder Singh Bhundar—not here. Shri Dara Singh Chauhan.

Alleged misuse of C.B.I. by central government to frame social workers and political leaders in false cases

श्री दारा सिंह चौहान (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम आपके माध्यम से सदन में एक बहुत गंभीर मसले पर चर्चा करना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आज तक जितनी भी सरकारें बनीं हैं, किसी भी सरकार ने सी॰बी॰आई॰ का दुरूपयोग नहीं किया, लेकिन वर्तमान जो सरकार है, वह सी॰बी॰आई॰ को एक हथियार के रूप में और अपने विरोधी राजनीतिक दलों के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उन्हें फर्जी मुकदमों में फंसाने के लिए, गलत तरीके से उसका दुरूपयोग कर रही है। जिस सी॰बी॰आई॰ पर आम जनता को भरोसा था, आज उस सी॰बी॰आई॰ से इस देश की जनता का भरोसा उठ रहा है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारी बहन, समाजवादी पार्टी की जो राष्ट्रीय उपाध्यक्षा हैं और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्य मंत्री रही हैं, उनको यह वर्तमान सरकार, सी॰बी॰आई॰ को एक हथियार बनाकर, गलत तरीके से मुकदमे में फंसाने की साजिश कर रही है और इस विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं।

मान्यवर, पहली बार वे मुख्य मंत्री बनीं उत्तर प्रदेश की ओर 17 अक्तूबर, 1995 को उन्होने रिज़ाइन कर दिया, लेकिन फ्लोटिंग पम्प केस में उनको फंसाने की साजिशें जारी हैं। 27 दिसम्बर, 1995 को प्रेज़ीडेंट रूल के समय, जब मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री नहीं रहीं, 300 पम्प का आर्डर किया गया। इसके बाद 20 मई, 1996 को तत्कालीन राज्यपाल ने 157 रुपए प्रति पम्प खरीदने का आदेश दिया और 31 मार्च तक सारे पैसे का भुगतान करने का भी आदेश दे दिया। इसके बाद जब दोबारा वह 21 मार्च, 1997 को मुख्य मंत्री बनीं तो उत्तर प्रदेश के 6 वरिष्ठ अधिकारी, जो उससे रिलेटिड थे, उनकी समिति बनाई गई और डेढ़ साल बाद, जबकि टेंडर काल किया गया था प्रेज़ीडेंट रूल में, जो 141 पम्प बाकी बचे रहे, उसके लिए 6 वरिष्ठ अधिकारियों की समिति बनाई गई और इस डेढ़ साल में जबकि महंगाई बढ़ी, रुपए का अवमूल्यन हुआ, इंटरनेशनल मार्किट में उस पम्प का भाव बढ़ा, इसके बावजूद भी मुख्य मंत्री रहते हुए उन्होंने, जिस रेट पर पूर्व राज्यपाल ने टेंडर किया था और खरीददारी की थी, उसी रेट पर उन्होंने उसे खरीदा। लेकिन, मान्यवर, 19 अक्तूबर, 1997 को जब हमारी नेता ने सरकार से समर्थन वापिस लिया तो ठीक उसके एक दिन बाद, अगले दिन, हमारे आज के जो मुखिया हैं उत्तर प्रदेश के, मुख्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने सैंट्रल गवर्नमेंट को लिखा कि इस मामले की सी॰बी॰आई॰ से जांच कराई जाए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 28 मार्च, 1998 तक यह मामला दर्ज नहीं हुआ, 6 महीने तक यह मामला दर्ज नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है? इससे साफ जाहिर होता है कि वर्तमान सरकार सी॰बी॰आई॰ को एक हथियार बनाकर इस देश में रहने वाले गरीब, दलित, शोषित समाज के लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों, चूंकि मायावती जी दलित समाज में पैदा हुई हैं इस नाते सारे मुल्क के दलित-शोषित वर्ग के लोग उनके पीछे खड़े हैं, इसलिए यह सरकार मायावती जी को बदनाम करके उस समाज के मनोबल को गिराने की साजिश कर रही है और सी॰बी॰आई॰ से जांच की बात कर रही है।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सी॰बी॰आई॰ कब हरकत में आई? 18 मार्च तक सी॰बी॰आई॰ हरकत में नहीं आई, मामला दर्ज नहीं हुआ, यह असत्य केस था। लेकिन जब प्रज़ीडेंट ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधान मंत्री बनने का और सरकार बनाने का न्यौता दिया, उसके बाद इस सरकार में जो जिम्मेदार लोग बैठे थे उन्होंने हमारी

90/RS/

बहुजन समाज पार्टी की नेता पर दबाव डाला कि आप सरकार को समर्थन दीजिए, लेकिन जब उन्होंने साफ इंकार कर दिया कि हम सरकार को समर्थन नहीं देंगे तब जाकर गलत तरीके से फंसाने के लिए सी.बी.आई. का सहारा लेकर यह सब किया जा रहा है ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आपका प्वाइंट हो गया।

श्री दारा सिंह चौहान: इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो वर्तमान सरकार है, दलित की बेटी को जब पहली बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, ऐसे लोगों को फंसाने की कोशिश यह सरकार कर रही है। मैं कहना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार दलित विरोधी है, पिछड़ा वर्ग विरोधी है। इनके शासनकाल में अल्पसंख्यकों की, दलितों की, पिछड़ों की, अकल्लियतों की हत्याएं हो रही हैं। उनका मान-सम्मान सुरक्षित नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले को गंभीरता से देखना चाहिए। सरकार आज सी.बी.आई. का दुरुपयोग कर रही है, सी.बी.आई. को हथियार बनाकर हमारे देश में रहने वाले दलित, शोषित समाज के जो लीडर हैं, उनके खिलाफ साजिश हो रही है। इस पर आप रोक लगाने की कार्यवाही करें।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): गांधी आजाद जी, आप एसोसिएट कर दीजिए।

श्री गांधी आजाद (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, वैसे तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है और उसका दर्द भी बहुत बड़ा है और इसके दर्द को भरे सदन में सुनाना चाहिए था लेकिन इस समय सदस्य कम हैं, फिर भी मजबूरी है, आपने हमें बोलने का मौका दिया है, इसके लिए आपका धन्यवाद, मैं उस दर्द के बारे में आपको कुछ सुनाना चाहता हूं। महोदय, 21 सितंबर, 1997 से उत्तर प्रदेश में भाजपा की जो सरकार है, तब से लगातार वहां दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उसका मैं खुलासा करना चाहता हूं। महोदय, 21 सितंबर को मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठते हैं और 22 सितंबर को ही जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है, जो केन्द्र सरकार का अधिनियम है, उसको शिथिल करने के लिए 22 तारीख को ही मुख्यमंत्री एक शासनादेश जारी करते हैं जिसके द्वारा आज ऐसा हो गया है उत्तर प्रदेश में कि सरेआम दलित समाज के लोगों का कत्ल किया जा रहा है, इज़्ज़त लूटी जा रही है लेकिन एफ.आई.आर. तक दर्ज़ नहीं हो रही है।

महोदय, उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी बहादुर है कि उनकी बहादुरी केवल यहां तक सीमित रह गई है कि जब भी मामला उठता है, कहीं जघन्य अपराध होता है तो अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि आधे घंटे बाद पुलिस ने पहुंचकर लाश को अपने कब्ज़े में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके अलावा वह कुछ नहीं कर पाती है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि जो यह दलित विरोधी सरकार है, इसके द्वारा भारत सरकार द्वारा पोषित स्पैशल कंपोनेंट स्कीम और ट्रिब्यूनल स्कीम को भी खत्म कर दिया गया। आरक्षण व्यवस्था में एक पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जो एकल पद में रोस्टर प्रणाली की गई थी, उसको भी खत्म कर दिया गया है। मेडिकल में एम.डी., एम.एस. और एम.एस.(डैंटल) में 20 प्रतिशत अंक ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) हो गया, हो गया। आप स्पैशल कंपोनेंट को इसमें क्यों ला रहे हैं?

श्री गांधी आजाद: अभी कहां हो गया? एक मिनट और दीजिए। एम.एस.(डैंटल) में एडमीशन के लिए पात्रता 20 प्रतिशत अंक से 35 प्रतिशत अंक कर दी गई जिससे आज 100 छात्रों के स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। मछुआरों को मछली पालन का पट्टा दिया जाता था, उसको भी समाप्त कर दिया गया ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): यह सब नहीं आएगा इसमें। आप खाली एसोसिएट कर दीजिए।

श्री गांधी आजाद: महिला आयोग भी खत्म कर दिया गया। उसकी अध्यक्ष अनुसूचित जाति की महिला थीं ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): गांधी जी, यह सब इसमें नहीं आएगा। आप खाली एसोसिएट कर दीजिए।

श्री गांधी आजाद: अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को खत्म कर दिया गया जिसमें अनुसूचित जाति के लोगों को भरा जाता था। इसके अतिरिक्त हमारे साथी ने जो कुछ बताया है, मैं उनके साथ अपने को सम्बद्ध करता हूं। धन्यवाद।

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार): महोदय, हमारी बात का जवाब अभी तक नहीं मिला है। बहुत ज्यादती हो रही है यह सरकार नहीं सुनती है हमारी बात को ...(**व्यवधान**) हमने बिहार का, यू०पी० का मामला यहां उठाया है ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप लोग बैठिए, तब मैं बोलूंगा ना ...(व्यवधान) आप लोग नहीं बैठेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा ...(व्यवधान) आप लोग नहीं बैठेंगे तो मैं कैसे बोलूंगा ...(व्यवधान)

श्री नरेश यादव: आपके आदेश से हम तो बैठे रहते हैं ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): मैं बोल रहा हूं ना बैठिए।

श्री नरेश यादव: मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि बाढ़ पीड़ितों की सहायता करना सरकार का कर्तव्य है, धर्म है और इसलिए सरकार की ओर से अगर जवाब आ जाए तो सरकार का क्या जाता है? हम लोग सुबह से चिल्ला रहे हैं ...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप लोग बैठिए, तब बोलूंगा ना मैं उनको ...(व्यवधान)

श्री नरेश यादव: हम लोग सुबह से चिल्ला रहे हैं लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसका मतलब है कि सरकार को बिहार के बाढ़ पीड़ितों से, केरल के बाढ़ पीड़ितों से, पश्चिम-बंगाल के बाढ़ पीड़ितों से, उत्तर प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों से कोई मतलब नहीं है। इससे जनता बहुत परेशान है। भारत सरकार की निष्क्रियता के चलते और केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार के बाढ़ पीड़ितों की उपेक्षा के चलते हम आर०जे०डी० के सभी साथी सदन से वाक आउट करते हैं। बिहार के सभी साथी वाक आउट करते हैं।

(इसके पश्चात् कुछ माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE) IN THE CHAIR.

Revenue Loss Following Introduction of E.D.I. Scheme

SHRI SATISH CHANDRA SITARAM PRADHAN (MAHARASHTRA): Respected Vice-Chairman, Sir, I wish to submit through you to the Finance Minister the various anomalies that have resulted in the loss of more than Rs. 50,000 crores to the Government of India because of various flows in the export policies and the differences between the Commerce Ministry and the Finance Ministry in the interpretation of laws which has enabled unscrupulous businessmen to misuse these schemes and enabled evasion of rightful duty to be paid to the exchequer. It is also learnt though newspaper reports that the following schemes, namely, the Duty Exemption Entitlement Certificate Scheme (DEEC), the Value Based Advanced License Scheme (VBAL) and the Quantity Based Advanced Scheme introduced for enhancing our exports and foreign exchange have, in fact, become a tool to unscrupulous elements vis-a-vis genuine exporters to receive laundered, evaded narco money thereby helping the hawala receketeering trade to grow. I am very much sure that the House would also be astonished to know that the *modus operandi* which is being used to evade this income and the rightful duty to be paid to the exchequer is a common knowledge both to the enforcing authorities as well as to the traders involved in this trade. In addition to this, it is also learnt through reliable sources that the Department of Finance is trying to update the records of its department, specially that of the enforcing agencies from the existing Sperry Spool Computer System with a new E.D.I. system which, according to specialists in the field, have noticed some major flaws. Some of them are: (a) that the concept of the new system is lost as the data is not being stored centrally but at 29 different sites; (b) that the transmission of data is through a line which is slow and unreliable; (c) that they would be enhancing a disk-operated-system (DOS) which is actually outdated; and (d) that while switching from the existing system to the new system, the data transferring is not being monitored properly by vested interests in the department such that defaulters and pending cases data can be easily deleted thereby giving them a clean chit. Under these circumstances, I would like to know from the Minister—(1) How many cases of fraud and default have been deleted specially with reference to DEEC, VBAL and QBAL schemes. (a) What is the total quantum of revenue actually involved in these frauds?